जल गाँव सफाई व बेकारी

इन चार क्षेत्रों में समस्याएं हैं। भारत में ही नहीं वरन् हरेक देश में कम या अधिक मात्रा में ये मौजूद हैं और समुचित प्रयास द्वारा इनका समाधान सम्भावनाओं में बदला जा रहा है। अगर भारत में इन चारों को एक साथ रखकर सोचा जाए तो ये सम्भावनाओं की आधारशिला बन सकता है। पर इसके लिए एकता, विश्वास, सरकारी एवं सहभागिता क्षेत्र के प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ज्यादातर गांवों में अशिक्षा, बेरोजगारी, जल की कमी के फलस्वरूप गन्दगी की भीषण समस्या है।

अब समय आ गया है कि हमें इनको सुलझाना ही पड़ेगा। हर गांव में पानी के संसाधनों की गणना हो व वर्तमान हालातों का लेखा-जोखा रखा जाए जिससे उनका पुनर्उद्धार हो सके। इसके लिए कुछ गांवों में पानी की समितियां हैं। जरूरत है कि ये समितियां हरेक गांव में हों और उनके पास अधिकार व पर्याप्त साधन हों जिससे वे सुचारू रूप से गांव की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकें चाहे वह पीने के पानी की हो या सिंचाई आदि की।

जैसे शहरों में पानी की आपूर्ति के लिए जल विभाग है, वैसे ही गांवों में भी पानी की आपूति की कम्पनियाँ बनाई जायं जिनमें बेरोजगार युवक-युवतियों को नियुक्त किया जाये। यह सब कार्य व्यवसायिक स्तर पर ही हो ताकि गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रह सके। इस तरह गांवों का पैसा गांवों में ही रहेगा और गांव की सम्पन्नता बनी रहेगी। पानी का व्यापार हो रहा है परन्तु व्यापारिक नियमों के विपरीत सामूहिक रूप से नहीं हो रहा है क्योंकि हम सामूहिक तरीके से कार्य करने के आदी नहीं हैं। गांवों में स्थिति यह है कि जहाँ भी पानी की कमी है वहाँ अमीरों को पानी सस्ता व गरीबों को महंगा मिलता है, वर्तमान व्यवस्था के फलस्वरूप। जबकि इससे उल्टा होना चाहिए। गरीब पिस रहे हैं। उन्हें इस स्थिति से उबारना होगा ताकि वे सही कीमत देकर आवश्यकता के अनुरूप जल का इस्तेमाल कर सकें।

समय की जरूरत है, आम आदमी की आर्थिक स्थिति को सुधारने की। न कि जल के क्रय-विक्रय को रोकने की। भारत एक जल-प्रधान, कृषि प्रधान देश रहा है और जल पिलाना पुण्य का काम माना जाता रहा हैं वह बात तो अब रही नहीं यह भावुकता गांवा वालों पर थोप जल का गांवों में सही क्रय-विक्रय न होने देना अपराध है जबकि शहरों में पीने के पानी का खुला व्यापार होता है। अब सफाई को लें। आज ''सफाई'' सिर्फ एक वर्ग की रोटी-रोजी ही नहीं वरन् उनकी बपौती बनकर रह गई हैं और यह स्पष्ट है, चारों तरफ फैली गन्दगी को देखकर कि यह उनके बस की बात नहीं रह गई है। इस क्षेत्र में उचित आर्थिक व बौद्धिक विनियोग के अभाव के कारण हम बहुत सी अच्छी सम्भावनाओं से वंचित रह गये और हम सफाई में पिछड़ते चले गये। इस वर्ग के ठेकेदार काम सही न कर पाने की अपनी असमर्थता को स्वीकार भी नहीं करते हैं और न ही किसी और को यह काम करने देंगे। यह एक भयंकर समझौता है जिससे सभी का नुकसान भरपूर हो रहा है। जनसाधारण का स्वास्थ्य गिर रहा है और बीमारियाँ मुंह बाए हमारे समाज को खा रही हें जो हमें दिखाई देती हैं पर हम सब हाथ पर हाथ धरे देख रहे हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण के लिए उंगलियाँ उठा रहे हैं। सोचते हें हम क्या करें। पर इसी से तो समस्याओं का हल निकलने वाला नहीं है। आप यदि रोज गन्दगी करेंगे तो रोज सफाई का काम भी करना होगा पर हम सफाई में पिछड़ रहे हैं व गन्दगी करने में आगे बढ़ रहे हैं। नतीजा, हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे में गन्दगी के ढेर व कीचड़ बढ़ती जा रही है। कहाँ फेकें इस बढ़ते कूड़े को यह भी अब समझ के बाहर है।

क्यों भई! हमारे यहाँ जब बिजली की कमी है और कूड़ा बहुतायत में है और कूड़े से बिजली भी बन सकती है तो क्यों न इसे जलाकर बिजली बनाने वाले प्लांट लगाए जाएं। कूड़े से ईंधन वाली गैस भी बनती है। यह शिल्प विज्ञान हमारे देश में आनंद, गुजरात में मौजूद है तो व्यवहार में क्यों नहीं आ सकता है?

इस समस्या का हल दो लाभों को देने वाला है। एक तो बिजली की कमी दूर होगी, दूसरा ईंधन वाली गैस मिलेगी। रोजगार जो बढ़ेगा सो अलग, पर यह सरकार के करने की बात नहीं है। गैर सरकारी स्तर पर गांवों

में कस्बों में व शहरों में भी इस प्रकार की कम्पनियां बनाई जाएं ताकि बेकारी भी दूर होगी और गन्दगी भी। आवश्यकता है तो प्राथमिकता तय करने की और इस दिशा में प्रोत्साहन की। कौन करे? जिनको जरूरत है काम की वे पहले करें। रोड़े आयेंगे, उन्हें दूर करना होगा पर सफलता मिलते ही कदम आगे बढ़ते जाएंगे। यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जायेगी और हमारा देश स्वस्थ, सुंदर व स्वच्छ बनेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए लेखक से सम्पर्क कर सकते हैं।

कम्पनियाँ शहरों में ही क्यों गाँवों में क्यों नहीं बन रहीं? यह सवाल कभी आपके मन में भी उठा होगा, उसका जवाब भी मिला होगा पर आगे मन में आएगा कि हम क्यों करें पहल? हमारे पापा के फलाने रिश्तेदार हमें तो नौकरी दिला ही देंगे। दूसरों से हमें क्या लेना देना। जो बेकार बैठे हैं वो असफल होने पर गिरे भी तो उससे बुरा क्या होगा, जो इस समय हो रहा है। सरकार, जल, बेकारी व सफाई की समस्या हल करने में विफल है। यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है। अत: हमें दूसरे विकल्प निकालने होंगे। हमें मदद मिलेगी यदि हम एक-एक कदम इन समस्याओं को हल करने की दिशा में उठाएंगे, क्योंकि कोई रास्ता चाहे कितनी भी दूरी वाला हो, उसकी तरफ एक बार में एक कदम उठाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यदि हम कदम उठायेंगे ही नहीं तो मंजिल खुद चलकर हमारे पास तो आने से रही। हमें चलने का काम खुद करना होगा यदि हम मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। अपनी सोच के तरीके को बदलना होगा वरना जो हम अब तक करते आ रहे हैं वही करते रहें तो वही फल मिलेगा जो कि अब तक मिलता रहा है। बेकारी मुंह बाए खड़ी है। जल का अकाल है और गन्दगी हमें चारों तरफ से घेरे जा रही है।

भगवान कहते हें, जो मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी ओर चार कदम बढ़ाता हूँ। और सफलता का दूसरा नाम भगवान है। हम आजादी के 58 सालों में भली-भांति समझ चुके हैं कि सरकार ही हर समस्या का हल नहीं कर सकती। हम सरकार की नीतियों का विरोध करने के बजाय उनको अपना सहायक भी बना सकते हैं। विरोध में ज्यादा व सहयोग में कम शक्ति का व्यय होता है।

जिन गांवों में बिजली नहीं है, राजीव गांधी रोजगार योजना या खादी ग्रामोद्योग के तहत 50 हजार रुपये उधार लेकर वहां बैलों से चलने वाले जनरेटर का संयत्र लगाकर बिजली की आपूर्ति की जा सकती हैं इसलिए आवश्यकता है उद्यमी, कर्मठ, नवीन विचारों वाले साहसी व आशावान युवक-युवतियों के कर्मक्षेत्र में उतरने की। सूर्य-ऊर्जा से चलने वाले पम्पों से भूगर्भ कीगहराई में से जल निकाला जा सकता है क्योंकि हमारे देश में सूर्य ऊर्जा की प्रचुरता है। प्रारम्भ से इन सेवाओं का मूल्य लिया जाना चाहिए क्योंकि नि:शुल्क वितरण व्यापार के नियमों के विरुद्ध है। देखें गुण्डे लोग भी मुफ्त काम नहीं करते हैं, तो उनके कार्यों को व्यभिचार कहकर हम टाल देते हैं।

गांवों में लघु उद्योग-धन्धों व उसमें लगने वाले कारीगरों का प्रशिक्षण भी गांवों में करना होगा। ऐसा हो भी रहा है पर उसको और अधिक क्षेत्रों में अपनाना होगा। गांवों में पैदा होने वाले अनाज, मसालों, दालों की सफाई, पिसाई व पैकेजिंग की प्रक्रिया, गाँवों में ही होनी चाहिए ताकि गाँवों में उद्योग बढ़े और गांवों के नौजवान नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ न भागें। मूंगफली, तिल, सरसों आदि का तेल बनाने की प्रक्रिया गांवों में क्यों नहीं हो सकती, ये चीजें गांव वाले अधिक दाम देकर वापिस शहरों से क्यों लाते हैं?

इसके अलावा गांवों में इस्तेमाल होने वाली कॉपियां, खिलौने आदि गांवों में बनाए जा सकते हैं। और भी अनेक चीजें सोचिये क्या-कया और गांवों में बनाया जा सकता है। यही एक तरीका है गांवों को समृद्ध बनाने का कि वहाँ लोगों को रोजगार मिले, जिससे वे आत्मनिर्भर बनें।

—रश्मि उमेश रोहतगी
24161 नीलन ड्राईव नौवी(मि०) सं०रा०अ० 48374-3754
248-471-5786 e-mail : rurohatgi@yahoo.com
website : www.rurohatgi.com